अपराह्न 12.03 बजे

लोक लेखा समिति

सोलहवां प्रतिवेदन

श्री नारायण दत्त तिवारी (नैनीताल) : महोदय, मैं केन्द्र सरकार विनियोजन लेखा (नागरिक) 1996–97 के मामले में लोक लेखा समिति (तेरहवीं लोक सभा) का सोलहवां प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.03¼ बजे

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

अध्ययन दौरा प्रतिवेदन

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : महोदय, मैं (i) नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और (ii) गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड से संबंधित सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति का अध्ययन और प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) को सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.03½ बजे

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

विवरण

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : महोदय, मैं राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड से संबंधित सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (ग्यारहवीं लोक सभा) के सातवें प्रतिवेदन के अध्याय I में उल्लिखित सिफारिशों तथा अध्याय V में उल्लिखित सिफारिशों के संदर्भ में दिए गए अंतिम उत्तर के मामले में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.04 बजे

पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति

ग्यारहवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : अध्यक्ष महोदय, मैं पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति का 'पोटाश/पोटिशिक उर्वरकों की मांग, उपलब्धता और आयात' संबंधी ग्यारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.04½ बजे

महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति

पहला प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा (कनारा) : सदा की भांति, हम महिलाओं को अंत में ही मौका मिलता है।

महोदय, मैं 'ग्रामीण महिला विकासकारी योजना' विषय पर महिला अधिकारिता संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन (बारहवीं लोक सभा) में उल्लिखित टिप्पणियां/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के मामले में इस समिति का प्रथम प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्कण) प्रस्तुत करती हूं।

अपराह्न 12.05 बजे

प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य

जम्मू-कश्मीर में सरकार के शांति प्रयास

प्रधानमंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : अध्यक्ष महोदय, संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त होने और सांसदों द्वारा क्रिसमस के त्यौहार पर जाने से पहले मैं जम्मू व कश्मीर की स्थिति तथा नियंत्रण रेखा के पास की स्थिति के बारे में सरकार के मूल्यांकन से आप सभी माननीय सांसदों को अवगत कराना चाहता हूं।

19 नवम्बर को मैंने यह घोषणा की थी कि रमज़ान के पवित्र महीने में हमारे सुरक्षा बलों द्वारा आतंकवादियों के खिलाफ कोई सैनिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। मैंने यह भी आशा की थी कि नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ बंद होगी। इस पहल के बाद स्थिति में कुछ उत्साहजनक बदलाव आया है। तथापि, कुछेक दूसरे पहलुओं पर हमारी चिंता अभी भी बनी हुई है।

सरकार को जम्मू व कश्मीर राज्य के नागरिकों, राजनैतिक दलों और अन्य संगठनों की प्रतिक्रिया से काफी उत्साह मिला है। शांति की हमारी पहल का वहां व्यापक रूप से स्वागत किया गया है। अब उस राज्य में बिलकुल अलग और काफी अधिक आशावादी माहौल दिखाई देने लगा है। राज्य में शांति बहाली में रुचि रखने वाली ताकतों में काफी वृद्धि हुई है।

उस राज्य में आतंकवादी हिंसा की घटनाओं में भी कमी हुई है। हालांकि लश्कर–ए–तौएबा और हरकत–उल–मुजाहिदीन जैसे संगठनों की गतिविधियां अभी भी जारी हैं जिसके कारण

न केवल निर्दोष नागरिकों की जानें गई हैं, बल्कि हमारे सुरक्षाकर्मियों की भी हत्याएं हुई हैं जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और खेदजनक है। सरकार इन और अन्य चुनौतियों का सामना करने और उनके अमानवीय और घृणित कृत्यों को रोकने के लिए दृढ़संकल्प है।

आतंकवादियों द्वारा नियंत्रण रेखा को पार करने और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ की कोशिशों में भी काफी कमी आई है। यह घुसपैठ पूरी तरह से बंद होनी चाहिए। सरकार इसे रोकने के लिए प्रतिबद्ध है।

नियंत्रण रेखा के पास गोलाबारी की घटनाओं में काफी सुधार देखा गया है। शुरूआत में कुछेक घटनाओं को छोड़कर 19 नवंबर को मेरे द्वारा घोषणा किए जाने के बाद नियंत्रण रेखा के आसपास अपेक्षाकृत शांति का माहौल बना है।

इसलिए सरकार ने सभी पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद 'कोई सैनिक कार्रवाई न करने' की अवधि को एक और महीने के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है। सन् 2001 के गणतंत्र दिवस के बाद सरकार स्थिति की फिर समीक्षा करेगी।

पाकिस्तान के साथ बातचीत की प्रक्रिया भारत ने शुरू की थी। भारत इस पर कायम रहेगा। इस प्रकार की प्रक्रिया के लिए उपयुक्त वातावरण का होना बहुत जरूरी है। शिमला समझौते और लाहौर घोषणा-पत्र पर हमारी निष्ठा कायम है। इस निष्ठा के तहत हमारी सरकार ऐसे कदम उठाएगी जो आवश्यक समझे जाएंगे ताकि भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच संयुक्त बातचीत की प्रक्रिया फिर से शुरू की जा सके।

मैं सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि आतंकवाद की चुनौती का सामना करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता हमेशा बनी रहेगी। हालांकि अत्यधिक उकसाए जाने पर भी हम काफी संयम बरतते रहेंगे लेकिन राष्ट्रीय हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेंगे।

मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हम पूर्ण शांति बनाए रखने और जम्मू व कश्मीर के सभी नागरिकों को भारत की खुशहाली और प्रगति में बराबर का हिस्सेदार बनाने की अपनी प्रतिबद्धता पर कायम रहेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री कड़िया मुण्डा द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्ताव को छोड़कर कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 12.08 बजे

समिति के लिए निर्वाचन

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

[हिन्दी]

श्री कड़िया मुण्डा (खूंटी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा इस सभा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति की शेष अवधि के लिए चौधरी चुन्नीलाल के निधन के कारण रिक्त हुए स्थान पर समिति के साथ सहयोजित करने के लिए राज्य सभा से एक सदस्य को नाम-निर्देशित करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नाम-निर्दिष्ट सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा इस सभा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति की शेष अवधि के लिए चौधरी चुन्नीलाल के निधन के कारण रिक्त हुए स्थान पर समिति के साथ सहयोजित करने के लिए राज्य सभा से एक सदस्य को नाम-निर्देशित करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नाम-निर्दिष्ट सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : 'शून्य काल' की मेरी घोषणा के बगैर ही आपने मामलों को उठाना आरंभ कर दिया है।

(व्यवधान)

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा) : मैंने प्रतिदिन नोटिस

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।